दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd.No.-UPHIN/2004/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

धक-धक गर्ल के दीवाने थे लाखों, लेकिन इस... P-8

▸ वर्ष : 01 ▸ अंक : 04 ▸ गाजियाबाद, मई, 2018 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

सीएम बनते ही बीएस येदियुरप्पा ने किया किसानों का कर्ज माफ

-विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विश्वास जताया है कि वह सदन में बहुमत सिद्ध कर देंगे। ईश्वर व किसानों के नाम पर शपथ लेने के बाद मीडिया के सामने आए येदियुरप्पा ने किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की। कर्नाटक के 25 वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद येदियुरप्पा ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह राज्यपाल वजूभाई वाला के बहुमत सिद्ध करने के लिए दिए गए 15 दिन के समय से पहले ही सदन में विश्वासमत हासिल कर लेंगे।

कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीएस येदियुरप्पा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने चार आईपीएस अधिकारियों के तबादला का कर दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक के खुफिया प्रमुख को भी बदल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमर पांडे नए एडीजीपी (खुफिया) के प्रमुख होंगे।

बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने के बाद राज्य में राजनीतिक उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि बहुमत के जादुई आंकड़े का दावा पेश कर येदियुरप्पा को राज्य के गवर्नर वजुभाई वाला द्वारा सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद गुरुवार को उन्हें सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। इससे पहले कांग्रेस-जेडीएस की याचिक पर बुधवार देर रात तक विशेष सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग से इनकार कर दिया। कांग्रेस की अर्जी पर तीन घंटे से अधिक चली सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

हालांकि, इस मामले पर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे फिर तीन जजों की बेंच (जस्टिस भूषण, जस्टिस सीकरी और जस्टिस बोबडे) सुनवाई करेगी। जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा से विधायकों की लिस्ट भी मांगी है। कोर्टरूम में आधी रात को चली सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील रखी कि जब किसी दल के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल ने भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए क्यों आमंत्रित किया है। बीजेपी के पास सिर्फ 104 विधायक हैं। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सिंघवी कहा कि राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए पहली बार किसी दल को 15 दिन का वक्त दिया, जबकि येदियुरप्पा ने 7 दिन का समय मांगा था। सिंघवी ने कहा कि हमारे पास 117, जबकि बीजेपी के पास केवल 104 विधायक हैं तो फिर वह बहुमत कैसे साबित करेगी? उन्होंने कहा कि जब किसी दल के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल ने भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए क्यों आमंत्रित किया है। बीजेपी के पास सिर्फ 104 विधायक हैं। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। जब तक 8 विधायक उनके साथ नहीं जाते तब तक वह बहुमत कैसे साबित कर सकते हैं? इतने विधायकों का टूटना कानूनन मान्य नहीं है।

मोदी स्टाइल में दिखे येदियुरप्पा, विधानसभा में सीढ़ियों पर माथा टेका, ईश्वर व किसानों के नाम पर ली शपथ

येदियुरप्पा के पास विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय है। सदन में भाजपा के पास 104 विधायक हैं जो बहुमत के 112 के आंकड़े से आठ विधायक कम है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 222 सीटों के लिए मतदान हुआ था। जयनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार के निधन के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया जबकि आर आर नगर सीट पर कथित चुनावी कदाचार के चलते मतदान 28 मई के लिए टाल दिया।

कांग्रेस को मिला जेठमलानी का साथ, राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

राज्य विधानसभा के 15 मई को आये नतीजों में त्रिशंकु विधानसभा आने के उपरांत सरकार बनाने के लिए दो दिन चली उठापटक के बाद राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को बुधवार रात सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। येदियुरप्पा ने आज सुबह अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा को 104 सीटे मिली हैं। भाजपा को उम्मीद है कि 222 विधायकों के सदन में वह अपना बहुमत सिद्ध कर देगी। बहुमत के आंकड़े 112 के लिये कम पड़ रहे आठ विधायकों को भाजपा कैसे जुटायेगी, येदियुरप्पा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि यह मामला अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

पेट्रोल में साढ़े चार और डीजल में चार रुपये की इजाफे के लिए रहें तैयार

नई दिल्ली। पेट्रोलियम कंपनियों को कर्नाटक चुनाव से पहले का मार्जिन हासिल करने के लिए पेट्रोल में चार रुपये से 4.55 रुपये तक और डीजल में साढ़े तीन से चार रुपये तक की बढ़ोतरी करनी होगी। इस बीच, बृहस्पतिवार को पेट्रोल में 22 पैसे प्रति लीटर की मूल्य वृद्धि के कारण दिल्ली में इसकी कीमत 75.32 रुपये हो गई, जो पांच साल का उच्चतम स्तर है। डीजल में भी 22 पैसे की वृद्धि के कारण राजधानी में इसकी कीमत 66.79 रुपये हो गई। चुनाव खत्म होने के बाद से पेट्रोल में 69 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 86 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसके बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों को प्रति लीटर 2.70 रुपये का न्यूनतम मार्जिन भी नहीं मिल रहा है। इसके मद्देनजर उनका कहना है कि आने वाले हफ्तों में पेट्रोल में साढ़े चार रुपये और डीजल में चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करनी होगी।

कंपनियों का कहना है कि चुनाव से पहले 24 मई को आखिरी बार जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत 74.84 डॉलर प्रति बैरल थी जो अब बढ़ कर 83.30 डॉलर बैरल हो गई है। इसकी वजह से उनका प्रति लीटर मार्जिन घटकर 0.31 पैसे रह गया है। बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार 14 मई को पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्यवृद्धि की गई थी। इससे पहले मूल्य वृद्धि नहीं करने की वजह से कंपनियों को 500 करोड़ की चपत लग चुकी है।

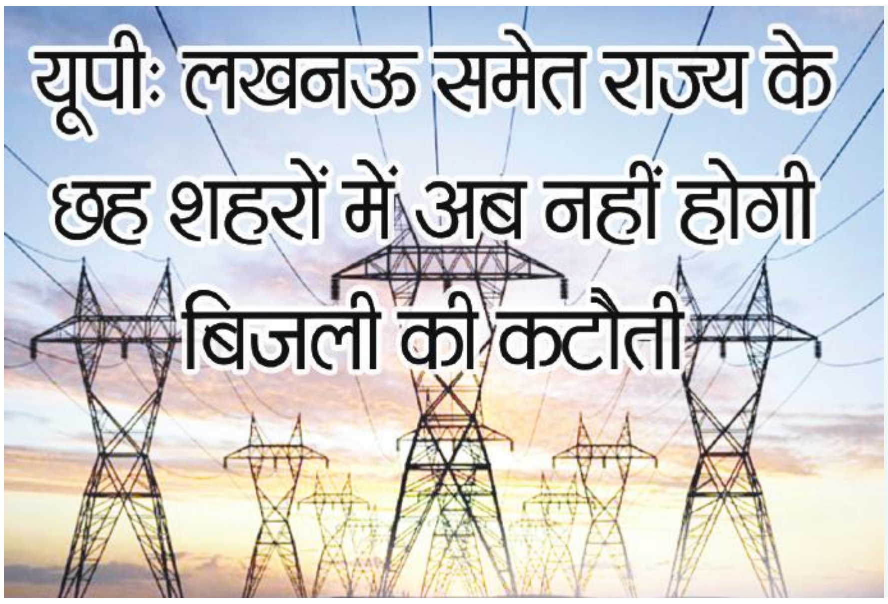

गाजियाबाद। यूपी के लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और गाजियाबाद में अब फाल्ट और ट्रिपिंग के कारण बिजली की कटौती नहीं होगी। यूपी पॉवर कारपोरेशन ने इसके लिए कार्य योजना बनाने शुरू कर दिया है।

प्रमुख सचिव ऊर्जा और चेयरमैन यूपीपीसीएल आलोक कुमार ने बिजली कटौती कम करने और सप्लाई बेहतर बनाने के संबंध में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कम से कम ट्रिपिंग हो और बिना कटौती बिजली सप्लाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती-ट्रिपिंग कम कर-के यूपी को देश में बिजली व्यवस्था में अव्वल नंबर पर लाने के लिए योजना तैयार करनी है। पहले चरण में जिन छह शहरों को ट्रिपिंग मुक्त किया जाना है उसके लिए सीएमयूडी के मुख्य अभियंता बीके सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वह इस संबंध में कार्य योजना की मॉनिटरिंग करेंगे। इन तय शहरों में शिड्यूल के अनुसार बिना कटौती बिजली सप्लाई की जाए। कुछ क्षेत्रों में परेशानी हो तो वहां ढांचागत विकास कराकर समस्याओं को दूर किया जाए।

❑ कम से कम ट्रिपिंग हो और बिना कटौती बिजली सप्लाई होनी चाहिए : आलोक

उन्होंने अफसरों से कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यूपी बिजली सप्लाई में तो अपनी रैंकिंग सुधार रहा है लेकिन अभी कटौती के मामले में यह पीछे है। प्रदेश के शहरों की रैंकिंग काफी नीचे है। यह अच्छे संकेत नहीं हैं। लखनऊ में भी 3.18 घंटे तक बिजली कट रही है। इसलिए एक्शन प्लान बनाकर कटौती को कम किया जाए।

❑ क्षेत्रों में परेशानी हो तो वहां ढांचागत विकास कराकर समस्याओं को दूर किया जाए

एक माह के अंदर यह तय कर लें कि अनावश्यक कटौती पूरी तरह बंद हो जाए। जहां एक बार लोकल फाल्ट हो जाए वहां स्थायी सुधार किए जाएं ताकि दोबारा समस्या न आए। एनर्जी ऑडिट के आधार पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ोत्तरी की जाए।

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General
w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	7613.42
Semi Skilled	8374.77
Skilled	9381.06

Engineering (50 to 500)
w.e.f. 01/02/2018 To 31/07/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8903.10
Semi Skilled	9776.65
Skilled	10853.64

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9333.89
Semi Skilled	10267.28
Skilled	11200.67

Delhi Minimum Wages
w.e.f. 01/04/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	16858.00
Semi Skilled	15296.00
Un-Skilled	13896.00

Rajasthan Minimum Wages
w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages
w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages
w.e.f. 01/03/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Highly Skilled	10561.17
Skilled	9529.17
Semi Skilled	8632.17
Un-Skilled	7852.17

Haryana Minimum Wages
w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

श्रम क्षेत्र में सुधारों से तीन साल में एक करोड़ रोजगार पैदा होने का अनुमान

नई दिल्ली। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत श्रम कानूनों में सुधार सहित विभिन्न नियामकीय सुधारों को आगे बढ़ाता है तो आने वाले तीन साल में बिक्री कारोबार के क्षेत्र में एक करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं. स्टाफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज ने एक रपट में यह निष्कर्ष निकाला है. फर्म की कार्यकारी उपाध्यक्ष ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा, केवल दस नियामकीय सुधार करते हुए हम अगले तीन साल में बिक्री करने के काम में एक करोड़ नौकरियां सृजित कर सकते हैं. यह भारत के लिये एक अवसर है, जो कि इस समय अहम जनसांख्यकीय मोड़ पर पहुंच चुका है. उन्होंने जिन सुधारों का जिक्र किया उनमें 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को केवल चार श्रम संहिताओं में सम्माहित करना, विशिष्ट उद्यम संख्या (यूईएन), कर्मचारी वेतन विकल्प, पीपीसी अनुपालन पोर्टल, कारखाना संशोधन विधेयक 2016, लघु कारखाना कानून में सुधार शामिल हैं. टिप्पणियां उन्होंने कहा कि शहरीकरण, मध्यम वर्ग के विस्तार, खुलकर खर्च करने वाली युवा पीढ़ी तथा सरकार की जीएसटी जैसी पहलों से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. चक्रवर्ती ने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाने की कंपनियों की योग्यता उनकी अधिक बिक्री करने, बेहतर बिक्री और तेजी से बिक्री करने की क्षमता पर निर्भर करेगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले मुंबई में ही अगले तीन साल के दौरान 3,60,000 के करीब बिक्री क्षेत्र में रोजगार पैदा हो सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार बिना सुधार के भी मुंबई में अगले तीन साल के दौरान 90 हजार के करीब नये रोजगार पैदा होंगे और बिक्री कारोबार में 15 प्रतिशत तक वृद्धि होगी.

बड़ी खबर: बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बीमार और बुजुर्गों को नहीं पड़ेगी आधार की जरूरत

नई दिल्ली। बैंक खाता खोलने के लिए अब बुजुर्ग, बीमार और घायल लोग आधार के अलावा अन्य पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने आज इस संबंध में अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। गजट अधिसूचना में कहा गया है कि धनशोधन रोकथाम नियमों में संशोधन कर पहचान स्थापित करने के वैकल्पिक तरीकों को मंजूरी दे दी गई है। यह वैकल्पिक तरीकों की छूट उन लोगों को प्राप्त होगी जो अपनी बायोमीट्रिक पहचान स्थापित करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह संशोधन घायल होने, बीमार होने या उम्र की वजह से बायोमीट्रिक पहचान स्थापित करने में असमर्थ लोगों को अन्य तरीके से पहचान जाहिर करने की अनुमति देता है। इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने कहा कि इस नियम से बुजुर्ग, घायल और बीमार लोगों को मदद मिलेगी।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT. LTD.

ISO 9001 : 2008

A COMPLETE H.R., LABOUR LAWS & PAY ROLL OUT SOURCING MANAGEMENT

When we are at your back please stopworrying about maintaining records of Factory Act, Shop & Commercial Establishments Act, Contract Labour and Abolition Act, ESIC Act, PF Act, (Boiler) IBR Act, and handling cases relating to Labour Commissioner Office. We feel ourselves much competent in solving such problems due to our sincere working and wide contacts.

We have a full-fledged office set-up having most modern communication facilities (LAN, e-mail, internet, fax, and integrated telecommunication system), fully computerized environment with highly qualified and competent staff to render efficient and prompt services to our esteemed clients.

Our company is the first ISO-9001:2008 CERTIFIED company in India in this category.

OUR SCOPE OF WORK -

We are committed to provide satisfactory services to the customers by delivering prompt & quality output at value prices. Our end-to-end service includes;

- Payroll
- TDS
- ESI Act
- EPF Act
- Minimum Wages Act
- Bonus Act
- Payment of Gratuity Act
- Standing Order
- Workmen Health & Safety Policy
- First Aid Training & Certificates
- Factory Plan & Site Plan
- Factory Act-1948
- Shop & Establishment Act

Our Website : www.legalipl.com, **CMD -** 9818036460 / 9818697406

H.O. : SH-295, 1st FLOOR, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD (U.P.) INDIA.
PH. : 0120-4122901, 4108794,
Mobile : 9910771102/04

B.O. : D-129, 1st Floor, Sector-10, NOIDA, GAUTHAMBUDH NAGAR, (U.P.) INDIA.
Ph. : 0120-4222307

E-mail : legalipl@yahoo.com, legaliplho@yahoo.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
दिल्ली–एनसीआर
गाजियाबाद, मई, 2018

कचरा समाधान महोत्सव में

नाडेप विधि से कम्पोस्ट बनाने का तरीका समझाया

गाजियाबाद। कविनगर रामलीला मैदान में कचरा समाधान महोत्सव संपन्न हुआ। प्रदेश के नगर विकास मंत्री व प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे उन्होंने कहा कि कचरे का निस्तारण आज बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद प्रशासन की इस दिशा में शुरू की गयी सकारात्मक पहल एवं सोच को आगे बढाने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाया जाये जिससे हर व्यक्ति अपने घर एवं मोहल्ले के कचरे को रिसाइकिंल कर उपयोग में लाए। वहीं डीएम ने बताया कि महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य शहर एवं गावों की गंदगी कचरा की रिसाइक्लि कर उपयोग में लाए जाने के लिए जागरूकता पैदा करना है। इसी बीच हमें भी कचरा समाधान महोत्सव में अपना प्रेजेंटेशन देने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्थान समिति ने भी नाडेप विधि से कम्पोस्ट बनाने का तरीका समझाया जो की बहुत ही सस्ता एवं टिकाऊ है इस विधि में बहुत ही कम लागत आती है जो की कोई भी आरडब्लूए या सोसाइटी कर सकती है तथा बायो डिग्रेडेबल कम्पोस्ट बना सकती है।

गाजियाबाद की जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी को इसके लिए बधाई दी। जिन्होंने इस तरह के आयोजन से लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री पूर्व जनरल वी.के. सिंह एवं उ.प्र. के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, खाद्य एवं रसद मंत्री अतुल गर्ग, विधायक सुनील शर्मा ने उत्थान समिति के स्टाल पर आकर प्रोत्साहित किया। एडीएम ज्ञानेंद्र सिंह, एसपी आकाश तोमर एवं एसपी मनीष कुमार मिश्रा, नगरायुक्त सीपी सिंह भी स्टाल पर पधारे। सभी से अनुरोध है की अपने-अपने क्षेत्र में ही यदि हम कचरा समाधान कर लेंगे तो हमारे देश से यह समस्या समाप्त हो जाएगी।

सम्पादकीय

मौसम की मार

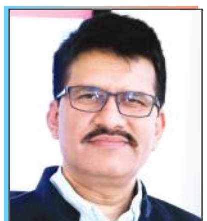

सत्येन्द्र सिंह

पिछले दो दशक में दुनिया के ऋतु-चक्र में आया बदलाव एक बहुत बड़े खतरे की आहट है। ठंड के मौसम में भी गर्मी का अहसास, बारिश के मौसम में कहीं भयंकर सूखा तो कहीं बाढ़, गर्मी में तेज आंधी और तूफानी बारिश यानी कुल मिलाकर मौसम चक्र गड़बड़ा गया है। गर्मी के मौसम में कश्मीर और हिमाचल में बर्फ पड़ रही है। जो समय उत्तर भारत में लू चलने का होता है, उस वक्त अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का यही आलम है। बारिश का मौसम आएगा तो मालूम चलेगा कि उमस भरी गर्मी पड़ती रही, पर पानी नहीं पड़ा और आखिर में सूखे की मार झेलनी पड़ी। दो दशक पहले अक्तूबर में ठंड पड़नी शुरू हो जाती थी और मार्च तक रहती थी। लेकिन अब पंद्रह दिन भी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती। मौसम में आ रहे इस तरह के बदलावों से पूरी दुनिया प्रभावित है। यूरोप और अमेरिका में सर्दी लंबे समय तक पड़ने लगी है, बर्फबारी होती है तो ऐसी कि पिछले सारे रेकार्ड टूट जाते हैं। अरब के मुल्कों तक से बर्फबारी की खबरें आ जाती हैं। समुद्र गरम होते जा रहे हैं और तटीय शहरों को आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में इनसान करे तो क्या करे, कुदरत की मार के आगे बेबस है। बिगड़ते मौसम को लेकर मौसम विभाग आए दिन आगाह कर रहा है। इस बार उत्तरी राज्यों में जिस तरह से अचानक मौसम बदला और तेज आंधी-बारिश से जो तबाही हुई, वह मौसम विज्ञानियों के लिए भी एक चुनौती है। पिछले हफ्ते उत्तर भारत को जिस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, उसमें मौसम तंत्र से जुड़ी कई घटनाएं ऐसी हुईं जो पहले कभी नहीं देखी गईं। मौसम विभाग इस तूफान को छोटे-से दायरेतक सीमित मान कर चल रहा था, लेकिन इसका दायरा बढ़ता ही गया और सही अनुमान नहीं लग पाया। हालांकि मई की शुरूआत में अंधड़ और बारिश को लेकर चेतावनी जारी हुई थी, लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बारे में यह नहीं थी। जबकि इन्हीं दो राज्यों में सबसे ज्यादा तबाही हुई। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तबाही का कारण हरियाणा के ऊपर बना चक्रवाती प्रवाह रहा। वैसे मई में ऐसा तूफान और ऐसी बारिश देखने को नहीं मिलती। जलवायु में तेजी से हो रहे छोटे-बड़े बदलाव ऋतु-चक्र को बिगाड़ रहे हैं। उत्तरी पाकिस्तान और राजस्थान में तापमान ज्यादा होने की वजह से गरम हवाएं ऊपर की ओर उठीं और कम दबाव का क्षेत्र बना। इसके साथ ही भूमध्य सागर और अरब सागर से चलने वाली पछुआ हवाओं से इस कम दबाव वाले क्षेत्र में बादल और चक्रवाती तूफान बना। मौसम में इस तरह के बदलावों के पीछे बड़ा कारण जलवायु संकट है। भारत में यह पहला मौका है जब मौसम को लेकर इतने व्यापक स्तर पर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग इस तरह के अनुमान उपग्रहों से मिले आंकड़ों और अन्य स्रोतों से हासिल जानकारियों के विश्लेषण के आधार पर व्यक्त करता है। ऐसे में संभव है कई बार अनुमान सटीक नहीं बैठ पाते। मौसम विभाग को देखना होगा कि वह अपने पूर्वानुमानों को और विश्वसनीय कैसे बना सकता है। आपदा से बचाव के लिए सही पूर्वानुमान पहला तकाजा है।

सरकारी बंगले को निजी जागीर समझने वाले नेताओं पर चला 'सुप्रीम' डंडा

सरकारी संपत्तियों और संसाधनों का दोहन करने में मुट्ठी भर लोगों को महारथ हासिल है। वर्ना आम आदमी जो इसके हकदार हैं वह तो एड़ियां घिसते-घिसते सरकार की 'चौखट' पर 'दम' तोड़ देता है। कहीं भी देख लीजिए हालात बद से बदतर नजर आयेंगे। हर तरफ अराजकता का बोलबाला है। काला-सफेद कोट पहनने वाले हों या फिर खादी अथवा खाकी में लिपटे लोग अथवा नौकरशाही या फिर बड़े-बड़े अन्य अधिकारी। सब सरकारी सुविधाओं का खूब फायदा उठाते हैं। सरकारी अस्पतालों में वीआईपी मरीज हाथों हाथ लिये जाते हैं। उन्हें डाक्टर अपने केबिन में बुलाकर देखता है तो गरीबों के नाम की दवाएं यह स्वयं डकार लेते हैं। यही स्थिति पुलिस चौकियों और थाने से लेकर प्रदेश के हाकिम तक के दफ्तर में नजर आती है।

यहां गरीब की रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है और 'पहुंच' वालों के आने पर 'रेड कार्पेट' बिछा दिया जाता है। ऐसे लोगों के कहने पर कभी-कभी तो भुक्तभोगी को ही उलटे केस में फंसा दिया जाता है। हाल ही में जिला उन्नाव में इसकी बानगी उस समय देखने को मिली थी जब सत्तारूढ़ दल के एक विधायक की घिनौनी हरकत को नजर अंदाज करके बलात्कार का दर्द झेल रही एक युवती पर अत्याचार के पहाड़ टूट पड़े थे। अदालत की चौखट पर भी ऐसा ही माहौल दिखाई पड़ता है। गरीब को तारीख पर तारीख मिलती रहती है और पॉवरफुल अपराधी तक पैसे के बल पर बेदाग बरी हो जाते हैं। जेलों में जाकर देख लीजिए कई छोटे-छोटे अपराध में फंसे कैदी वर्षों से इसलिये जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनक पास जमानत के लिये कुछ नहीं है। जबकि हनकदार लोगों के लिये कानून तक बदल दिये जाते हैं। जैसा कि 2016 में देखने को मिला था, जब अखिलेश सरकार ने कोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास खाली कराने के एक आदेश को पलटने के लिये नया कानून ही बना दिया था, लेकिन लम्बी लड़ाई के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित वह कानून निरस्त कर दिया जिसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले में रहने की सुविधा दी गई थी।

कोर्ट ने फिर दोहराया कि किसी को इस आधार पर सरकारी बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता कि वह पूर्व में किसी सार्वजनिक पद पर रह चुका है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी आशय का आदेश जारी किया था जिसे बेअसर करने के लिए तत्कालीन अखिलेश सरकार ने विधानसभा से नया कानून पारित करवाया। इस नए कानून को एक एनजीओ ने अदालत में चुनौती दी थी। दो साल बाद कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि चूंकि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए उन्हें आवास की सुविधा भी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इन बातों को सरकारी आवास आवंटित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की योगी सरकार का इस फैसले को लेकर क्या स्टैंड रहता है। वैसे सच्चाई यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा जितना उसके विरोधियों में शामिल मुलायम, मायावती और अखिलेश यादव के लिये रहेगा। यह सोच कर बीजेपी खुश भी हो सकती है क्योंकि पूर्व सीएम की लिस्ट में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्रियों कल्याण सिंह एवं राजनाथ सिंह का ही नाम शामिल है।

कायदे से तो 2016 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को स्वेच्छा से सरकारी बंगले छोड़ देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके उलट जब अखिलेश सरकार ने बंगले खाली कराने के बजाय संबंधित कानून में संशोधन किया तो बात-बात पर अखिलेश सरकार का विरोध करने वाली बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने इस तरफ से मुंह मोड़ लिया। इसे लोकतंत्र की विकृति के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा होगा अब ज्यादा थुक्का फजीहत न हो इसके लिये पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद बिना किसी देरी के खुद को आवंटित बंगले छोड़ दें। यह एक किस्म की सामंतशाही के अलावा और कुछ नहीं कि मुख्यमंत्री पद से विदा होने के बाद भी नेतागण सरकारी बंगलों को अपने पास रखे रहें।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवनभर सरकारी बंगलों में रहने की सुविधा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज करते हुए कहा है कि एक बार जब ऐसे लोग सरकारी पद छोड़ देते हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो उनमें और आम आदमी में अंतर करता हो। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली करने को कहा है, उनके पास अपने घर भी हैं। चुनावी हलफनामों के अनुसार मायावती के पास करोड़ों की संपत्ति के साथ दिल्ली और लखनऊ में अपने घर हैं। मुलायम सिंह के पास भी करोड़ों की सम्पत्ति के साथ इटावा, सैफई और लखनऊ में एक-एक घर है। राजनाथ सिंह के पास भी लखनऊ में अपना घर है।

पूर्व मुख्यमंत्रियों- नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम, मायावती, अखिलेश के नाम बंगले आवंटित हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का बंगला अब उनके ही नाम से बने एक ट्रस्ट के नाम है। इसी तरह हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर भी ट्रस्ट बनाया गया था। मायावती के बंगले को भी ट्रस्ट के नाम से आवंटित किया गया है।

बात पूर्व मुख्यमंत्रियों की हैसियत का की जाये तो यह लोग सरकारी बंगले में रहते तो जरूर हैं लेकिन इनके निजी घरों की भव्यता देखते बनती है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव के लिए तो उनकी ही सरकारों ने खजाने का मुंह खोल रखा था। अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले आधुनिक भले ही न हों लेकिन यह बंगले भी किसी से कम नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर प्रदेश में छह राजनेताओं पर पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव के पास भी सरकारी बंगला था लेकिन उन्होंने उसे खाली कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्रियों को इन बंगलों में जीवन भर रहने का अधिकार मिला हुआ था।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, हेमवतीनंदन बहुगुणा और श्रीपति मिश्र को भी बंगले मिले थे, मगर 1997 में हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद वीपी सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवतीनंदन बहुगुणा और श्रीपति मिश्र के आवास खाली हो गए थे, मगर मायावती की गठबंधन सरकार ने 'एक्स चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस अलाटमेंट रूल्स 1997' बना कर एक बार फिर बंगलों पर कब्जा जमाये रखने का इंतजाम कर दिया था। इस नियम के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले में जमे रहने का मार्ग निकल आया और पुराने नामों में मुलायम, मायावती, राजनाथ, कल्याण, अखिलेश आदि की श्रृंखला जुड़ती गई।

आतंकियों की प्रेमिकाएं बनीं मुखबिर, सुरक्षा बलों का काम हुआ आसान

कश्मीर में आतंकियों को प्रेमिकाओं से की जाने वाली बेवफाई भारी पड़ने लगी है। हिज्ब के दूसरे पोस्टर ब्वॉय आतंकी कमांडर समीर टाइगर की मौत का जिम्मेदार अब एक युवती को ठहराया गया है। सोशल मीडिया पर जारी उसकी तस्वीर के साथ उसे मुखबिर घोषित किया गया है जबकि सच्चाई यह है कि समीर ने इस युवती को प्यार में धोखा दिया था। वैसे कश्मीर में जारी आतंकवाद के इतिहास में यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें आतंकी कमांडरों की मौत का कारण युवतियां बनी हों। कई आतंकी कमांडर या तो अपनी प्रेमिकाओं से मिलने की चाहत के कारण डूब गए या फिर कइयों को उनकी उस बेवफाई के कारण जान से हाथ धोना पड़ा जो उन्होंने प्रेमिकाओं से की थी। ऐसे में गालिब का शेर याद आ जाता है जिसमें वे कहते थेः ह्यसच ही कहा है गालिब इश्क ने निकम्मा कर दिया वरना हम भी थे आदमी काम के। यह शेर कश्मीर में सक्रिय उन आतंकियों पर शत-प्रतिशत लागू हो रहा है जो जेहाद छेड़ने की मुहिम में जुटे हैं और अपनी प्रेमिकाओं से मिलने की चाहत में मौत को गले लगा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों पर यकीन करें तो पिछले 30 साल के आतंकवाद के इतिहास में ऐसे सैंकड़ों मामलों में सुरक्षाबल आतंकी कमांडरों और उनके काडर को मार गिराने में उस समय कामयाब हुए जब वे प्रेमिकाओं की गोद में सिर रख कर जन्नत का नजारा लूटने के इरादे से उनसे मिलने आए या फिर अपनी प्रेमिकाओं से बेवफाई के चलते उनकी प्रेमिकाओं ने उनकी मुखबिरी कर डाली। ताजा मामला हिज्ब के दूसरे पोस्टर ब्वॉय समीर टाइगर का है।

अगर जानकारों की बात को मानें तो वह मुठभेड़ वाले दिन अपनी दूसरी प्रेमिका से मिलने घर आया था तो उसकी पहली प्रेमिका ने उसकी मुखबिरी कर सेना को उसके प्रति जानकारी दे डाली थी। इससे पहले का एक बड़ा मामला वर्ष 2016 के जुलाई महीने में हिज्ब के पहले पोस्टर ब्वॉय बुरहान वानी का भी था। बुरहान भी अपनी गर्लफ्रेंड की मुखबिरी पर मारा गया था। दरअसल सूत्र बताते थे कि बुरहान ने कई महिलाओं और लड़कियों से संबंध बना रखे थे। सूत्रों का कहना था कि बुरहान से उसकी गर्लफ्रेंड नाराज थी।

मोबाइल पर उसकी चैटिंग भी देख ली थी उसकी गर्लफ्रेंड ने। इसके बाद से वह बदला लेना चाहती थी। इसी क्रम में उसने सुरक्षा एजेंसियों को उसके बारे में सटीक जानकारी दे दी थी। वैसे समीर टाइगर और बुरहान के मामले कोई पहले मामले नहीं थे कश्मीर के आतंकवाद के इतिहास में जबकि वे प्रेमिकाओं के कारण मारे गए हों बल्कि कुछ अरसा पहले श्रीनगर के शालीमार एरिया में लश्करे तौयबा के टाप कमांडर सलमान बट और बांडीपोरा में सैफुल्लाह को भी इश्क में मौत नसीब हुई और अगर जरा गौर करें तो जिस जेहाद का झंडा गाड़ने वे कश्मीर आए हुए थे वह इश्क को हराम कहता है। एक किस्सा काजी मुहम्मद का भी था। बारामुल्ला में उसे उस समय मार गिराया गया जब वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एलओसी को पार कर वापस कश्मीर लौटा था। अंततः वह उस समय मारा गया जब उसकी प्रेमिका उसे मिलने उसके ठिकाने पर गई तो सुरक्षाबल भी साथ ही पहुंच गए। फिलहाल सुरक्षाधिकारी यह बताने को राजी नहीं हैं कि उसकी प्रेमिका का क्या हुआ। अगर सुरक्षाधिकारियों पर विश्वास करें तो काजी मुहम्मद अपनी प्रेमिका से सख्त नाराज भी था क्योंकि वह युवती उससे मिलने उसके ठिकाने पर नहीं जाना चाहती थी और काजी मुहम्मद के मोबाइल फोन की रिकार्डिंग उसके गुस्से को इस प्रकार इजहार करती थीः मैं खतरे मोल लेकर एलओसी की बारूदी फिजां को पार कर आया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम दो कदम भी नहीं चल सकती।

माँ विन्ध्यवासिनी के आँचल में संरक्षित है गौरैया...

चूँ चूँ करती, धूल नहाती गौरैया.
बच्चे, बूढ़े, सबको भाती गौरैया.
कभी द्वार से, कभी झरोखे, खिड़की से
फुर-फुर करती, आती जाती गौरैया.
बीन-बीन कर तिनके ले-लेकर आती
लकड़ी के बने घोषले में नीड़ बनाती गौरैया....

ये सब शब्द किसी कविता के नहीं ये सब सजीव दृश्य आप देख सकते हैं माँ विन्ध्यवासिनी के आँचल विन्ध्याचल के शेरकोठी में आकर जो माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर के पास ही स्थित है और गौरैया संरक्षण में अपना राष्ट्रीय पहचान बना चूका है। इस शेर कोठी के त्रियोगी नारायण मिश्र ऊर्फ मिट्ठू मिश्र अपने स्वयं सेवी संस्था विन्ध्य सेवा मंच के द्वारा गौरैया संरक्षण का प्रचार प्रसार कर रहें हैं। गौरैया से त्रियोगी नारायण मिश्र उर्फ मिट्ठू मिश्र को शांति-खुशी के साथ-साथ एक पहचान भी मिली है. आज मिट्ठू मिश्र उत्तर प्रदेश के, 'स्पैरो मैन' के नाम से जाने जाते हैं. इन्हें इस काम के लिए कई सामाजिक संस्था ने पुरष्कृत किया है पिछले वर्ष एक संस्था ने इन्हें 'हीरो ऑफ द इनवायर्मेंट' पुरष्कार से पुरष्कृत किया था। एक समय जब उत्तर प्रदेश सरकार का पर्यावरण एवं वन विभाग सरकारी आवासों में गोरैया के लिए घोंसला लगाने की योजना पर काम कर रहा था तब उसने इस काम में मिट्ठू मिश्र की भी मदद ली थी और इन्हों ने राज्य सरकार की 20मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उत्तर प्रदेश गिविंग विंग्स टू द स्पैरो में 8 मिनट मिट्ठू मिश्र का वक्तव्य और इनके विन्ध्याचल स्थित आवास शेरकोठी पर गौरैया के घोंसले और गौरैया बचाओ अभियान की सम्पूर्ण गतिविधि को प्रमुखता से दिखलाया गया जो एक बड़ी उपलब्धि है।

मिट्ठू मिश्र शेर कोठी के गौरैया संरक्षण पर आज की उपलब्धि का सारा श्रेय अपने पिता वीरेंद्र मिश्र को देते हैं और बताते है इनके निवास शेरकोठी पर गौरैया 1990 से संरक्षित है। गौरैया के संरक्षण की कहानी भी हृदय को छूनेवाली है माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर से उत्तर बगल स्थित शेरकोठी के स्वर्गीय वीरेंद्र मिश्र जो एक धर्म पुरुष और पक्षी प्रेमी थे सुबह सायं पक्षियों को दाना पानी देना उनकी दैनिक दिनचर्या में सामिल था रोज सुबह वो पूजा करने

से पहले चिड़ियों को दाना डालते जिससे वो चिड़ियों के हितैषी हो गए मिश्र जब खाना खाने जमीन पर लकड़ी के पीढ़े पर बैठते तो चारो ओर उन्हें गौरैया घेर लेती तब वो चारो ओर पके चावल के दाने भात को फेकते जिसे चिड़िया चाव से खाती वीरेंद्र मिश्र के बड़े सुपुत्र त्रियोगी नारायण मिश्र मिट्ठू जिन्होंने अपने पिताजी के गौरैया बचाओ अभियान संकल्प को सफल बनाने और उसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक सफलता पूर्वक पहुँचाने और लोगो को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित कर जोड़ने में लगे हैं वो अपने पिताश्री की कहानी बताते हुए कहते है उनके पिताजी का पक्षियों को दाना पानी रोज देने का सिलसिला यू ही चलता रहा और उनका पक्षी प्रेम तब परवान चढ़ने लगा जब उनके पिता जी के पूजन कक्ष में दो गौरैया का जोड़ा घोसला बनाकर रहने लगी और कुछी दिन में उस घोसले से झाँकने लगे दो चूजा अब चूजों के माँ बाप गौरा और गौरैया उसे दाना चूँगाने लगे ये प्राकृतिक दृश्य उनके पिता वीरेंद्र मिश्र के मन को हषार्ने लगे मार्च 1990 में उनके पिताश्री वीरेंद्र मिश्र पर तब वज्र का पहाड़ टूट गया जब उनके कमरे में लगे पंखे से चूजों की माँ गौरैया का सर पंखे से कट गया यह दृश्य देख उनके आंखों से बहने लगी न थमने वाली आँशु की धारा बिन माँ के बच्चों को देख चहकने लगा चूजों का बाप बेचारा इतने में उनके पिता वीरेंद्र मिश्र ने पास पड़े डंडे को पंखे की तार पर दे मारा पंखे की तार तोड़ अपना गुस्सा उतारा और वह जोर जोर चिल्लाने लगे आवाज सुन लोग वहाँ आने लगे वह बोले ताड़ के पंखे हाथों में होंगे ये कातिल पंखे बंद हो जाएंगे जब तक ये चूजे बड़े होकर न उड़ जायेंगे पूजा कौन करता वीरेंद्र मिश्र का अब तो चूजों पर ही सारा ध्यान टिका था मिले समय पर उन्हें दाना पानी चूजे भरे अपनी पहली उड़ान बस मन में यही सपना था जैसे जैसे चूजों के पंख फड़फड़ाने लगे वीरेंद्र मिश्र के मन हषार्ने लगे जिस दिन चूजे बड़े होकर उड़ गए उसदिन उनको मानो दुनिया के सारे दौलत मिल गये अब क्या था उनके निवास शेरकोठी की दिवालो पर इन नन्हीं पक्षी के लिये घोषले टंग गए और जगह जगह इनके लिए दाना पानी के व्यवस्था हो गए वीरेंद्र मिश्र 2005 में स्वर्गवासी हो गए लेकिन उन्होंने जो गौरिया संरक्षण के लिए संकल्प लेकर जो जलाई मशाल वो मिसाल बन गया और गौरैया संरक्षण में उनका निवास शेरकोठी राष्ट्रीय पहचान बन गया उनके संकल्प की सफलता का एहसास आप आज भी कर सकते हैं विन्ध्याचल की घनी बस्ती में स्थित उनके निवास शेरकोठी में आकर आज भी चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं।

मिश्र ने गौरैया की गतिविधियों पर काफी अध्ययन के बाद इनके अनकूल वैज्ञानिक तरीके से लकड़ी के घोषले भी तैयार किये हैं जिसमें गौरैया कम तिनकों में अपना घोषला बना लेती है साथ ही इसके प्रवेश द्वार को सिर्फ गौरैया के जाने के आकार का बनाया गया है साथ ही इस घोषले में गौरैया अपने चूजो को आशानी से दाना चुँगा सके इसके लिए घोषले में आगे एक प्लेटफॉर्म बनाये गए है और दूसरे बड़े पक्षी इन घोषलो पर न बैठे ताकि गौरैयों को दिक्कत हो इसके लिए घोषले के ऊपरी सतह छत को स्लोपिंग बनाया गया है।

मिट्ठू मिश्र के अनुसार यदी गौरैया नहीं बची तो हम सबको भविष्य में ऑक्सीजन मास्क लगाना होगा।

गौरैया है तभी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले दो पेड़ धरा पर मौजूद है बरगद और पीपल। गौरैया जब बरगद पीपल के फल को खाती है और उसे अपने पाचन तंत्र से गुजार कर बीट करती है तो ही इन वृक्षों का अंकुरण होता है इस लिये हम बरगद पीपल को बचाने के लिये गौरैया पक्षी को बचाने की अपील कर रहें हैं ताकि हमारे धरा पर ऑक्सीजन की कमी न हो साथ ही मिट्ठू मिश्र ने कहा की गौरैया को अपने निवाले में से दें सिर्फ दो चार दाना अपने घरों में बनाइये इनके लिये एक छोटा सा आशियाना ताकि किताबों में नहीं हकीकत में देख और सुन सके इनका चहचहाना-

त्रियोगी नारायण मिश्र (मिट्ठू मिश्र) गौरैया संरक्षक
शेरकोठी विन्ध्याचल मिजार्पुर उत्तर प्रदेश

कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन

गाजियाबाद। छठे वेतनमानों की वेतन विसंगतियों को दूर करने व सेवानिवृति की आयु बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर नगर निगम व राज्यकर्मचारियों ने कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनरतले सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। 7 वें वेतनमान राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकाय व सावजनिक निगमों एवं उपक्रमों व विकास प्राधिकरणों पर एक साथ लागू किए जाने समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारी- शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 31 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि छठे वेतनमानों की विसंगतिया हैं। इनको दूरने के बाद ही एक साथ ही स्थानीय निकाय के कर्मचारियों पर लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में निगमों के कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष करने, समस्त कर्मचारियों व शिक्षकों की सेवानिवृति 62 वर्ष करने, नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने, परिवहन निगम के कर्मचारियों को छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने, सभी कार्यरत तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को विनियमित करने, सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को गंभीर रोगों से इलाज के लिए कैशलेश की व्यवस्था करने, कलेक्ट्रेट को जनपद सचिवालय घोषित करने, पदों को तुरंत भरने, कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के दस प्रतिशत पदों पर पदोन्नति का कोटा निर्धारित करने समेत की मांगे शामिल हैं। संयोजक राकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यदि उनकी उक्त मांगों पर सरकार जल्द गंभीरता के साथ निस्तारण नहीं करती तो आगे जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पुनीत दीक्षित, सेवाराम शर्मा, महावीर त्यागी, हरेंद्र नागर आदि समेत सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे।

अब सड़क के किनारे पर लग सकेगी केवल छिद्रदार टायल्स

गाजियाबाद। प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया है कि अब सड़क के किनारे पर केवल छिद्र वाली टायल्स ही लगाई जा सकेगी ताकि बारिश का पानी जमीन के अंदर जा सके। इसके अलावा शासनादेश में और भी कई व्यवस्थाएं दी गई है। बता दें कि नगर निगम व जीडीए व अन्य संस्थाओं द्वारा सड़कों के किनारे, पार्कों में फुट पाथ आदि कंक्रीट से बनी टाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा था। पर्यावरणविद्व आकाश वशिष्ठ ने इसको लेकर काफी विरोध किया था लेकिन नगर निगम व जीडीए के अधिकारियों ने इसको तवज्जो नहीं दी थी। जिसके बाद उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) दरवाजा खटखटाया था और याचिका दायर की थी। जिसके बाद एनजीटी ने इसको लेकर एक पॉलिसी बनाने की निर्देश दिए थे। बाद में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर विश्वजीत भटटाचार्य की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में जीडीए के अधिशासी अभियंता, उद्यान अधिकारी, उप नगर आयुक्त तथा आकाश वशिष्ठ को शामिल किया गया था। जिलाधिकारी को भी इस कमेटी में शामिल किया गया था। कमेटी गठन होने के बाद लंबे समय तक जब इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आकाश वशिष्ठ ने एनजीटी में अवमानना की याचिका डाल दी। इसके बाद एनजीटी ने संबंधित विभागों को जमकर

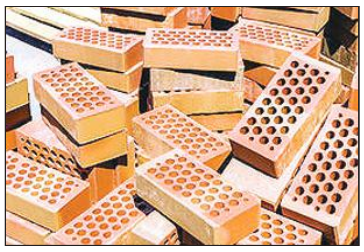

हड़काया जब आगे बात बढ़ी और यहां से एक पालिसी बनाकर प्रदेश सरकार को भेजी गई। इसमें कई तकनीकि सुझाव दिए गए। इसके बाद अब प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया है जिसके अनुसार अब प्रदेश में सड़क के किनारों पर केवल छिद्रवाली टायल्स ही लग सकेगी। इतना ही नहीं पार्क में केवल पांच प्रतिशत ही फुटपाथ का निर्माण किया जा सकेगा। फुटपाथ केवल कच्ची मिटटी का ही बन सकेगा। इतना ही नहीं शासनादेश के तहत सड़कों के दोनों किनारों पर .25 मीटर ही भूमि पर छिद्रवाली टाइल्स लगाई जा सकेगी। जलाश्यों, तालाबों व झीलों के चारों मिटटी का पुश्ता बनाकर अधिकतम 2.10मीटर चौड़ाई में फ्लाई एश, ब्रिक स्ट्रेट आवेर ब्रंट ब्रिक या परमिएबल या सेमी परमिएबल छिद्रवाली टाइल्स लगाई जा सकेगी। आकाश वशिष्ठ का कहना है कि अब शासनादेश जारी होने के बाद निश्चित तौर पर इस पर अमल होगा और पर्यावरण को सरंक्षण होने में मदद मिलेगी।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

इलाहाबाद बैंक सीईओ और 2 पीएनबी निदेशकों को हटाने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू की

नई दिल्ली। सरकार ने इलाहाबाद बैंक की सीईओ और एमडी उषा अनंथसुब्रमण्यम और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो कार्यकारी निदेशकों को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। यह कार्यवाही हीरा कारोबारी नीरव मोदी के साथ मिलकर 2 बिलियन डॉलर के फ्रॉड में शामिल होने के संबंध में की जा रही है। गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी (गीतांजलि जेम्स के प्रमुख) मुख्य आरोपी हैं।

सरकार की ओर से यह कदम सीबीआई की ओर से इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल करने के बाद आया है। देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले के संबंध में पीएनबी के बोर्ड ने अपने दो कार्यकारी निदेशकों के वी ब्रह्माजी राव और संजीव शरण से सभी वित्तीय और कार्यकारी अधिकार वापस ले लिए हैं। वहीं इलाहाबाद बैंक का बोर्ड आज अपनी सीईओ और एमडी उषा अनंथसुब्रमण्यम से सभी अधिकार वापस ले सकता है। वो बीते साल 5 मई तक बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर रही थीं। आपको बता दें कि पीएनबी घोटाले की शुरूआत साल 2011 में हुई थी और यह घोटाला साल 2018 में खुलकर सामने

आया। इससे पहले पीएनबी बोर्ड ने सरकार की ओर से नामित डायरेक्टर के निर्देश पर एक आपात बैठक बुलाई थी। बीएसई स्टॉक एस्कचेंज में की गई फाइलिंग में पीएनबी ने बताया, इस मामले में हालिया डेवलपमेंट को देखते हुए इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि कार्यकारी निदेशक केवी ब्रह्माजी राव और संजीव शरण से सभी अधिकार वापस ले लिए जाएं और वित्तीय सेवाओं विभाग से उनके प्रतिस्थापन की मांग की गई है।

सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीटः

सीबीआइ ने पीएनबी घोटाले में गिरफ्तार आरोपितों की रिहाई रोकने के लिए पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में नीरव मोदी और उसकी कंपनियों के साथ-साथ पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपित किया गया है। आरोपपत्र में पीएनबी की तत्कालीन एमडी और सीईओ उषा अनंतसुब्रमण्यन की भूमिका का विस्तार से जिक्र किया गया है। वर्तमान में उषा इलाहाबाद बैंक की एमडी और सीईओ हैं। फिलहाल मेहुल चोकसी और उसकी कंपनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सीबीआइ का कहना है कि घोटाले में आरबीआइ के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। मुंबई की विशेष अदालत में सोमवार को दाखिल चार्जशीट के अनुसार, नीरव की कंपनियों को बिना किसी मंजूरी और बिना किसी गारंटी के लेटर आफ अंडरस्टैंडिंग (एलओयू) जारी करने में पीएनबी के ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी शामिल थे। सीबीआइ ने उषा अनंतसुब्रमण्यन से लेकर सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज करात समेत बैंक के कुल 12 अधिकारियों और कंपनियों को आरोपित किया है। चार्जशीट में नीरव मोदी, उसके भाई निशाल मोदी, उसकी तीन कंपनियों, इन कंपनियों में काम करने वाले सात अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है। इन कंपनियों को 6,500 करोड़ रुपये का एलओयू जारी किया गया था। मेहुल चोकसी की कंपनियों की खिलाफ चार्जशीट बाद में दाखिल की जाएगी।

हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट जल्द होगी लॉन्च, विटारा ब्रेजा से होगा मुकाबला

नई दिल्ली। हुंडई अपनी क्रेटा के फेसलिफ्ट वर्जन को जल्द लॉन्च करने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट को केरल स्थित डीलरशिप पर देखा गया है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के प्रति ग्राहकों के रुझान को देखते हुए हुंडई के कई डीलर्स ने इसकी बुकिंग भी 11 हजार रुपये से लेकर 51 हजार रुपये तक की राशि लेकर शुरू कर दी है। मौजूदा क्रेटा की भारत में कीमत 9.29 लाख रुपये से लेकर 13.03 लाख रुपये तक है। वहीं, हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट की अनुमानित कीमत 9.35 लाख रुपये से लेकर 13.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने इसमें अपडेटेड कास्केडिंग ग्रिल, नए प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, नए फॉग लैंप्स और नए डुअल-टोन मशीन कट एलॉय व्हील्स दिए हैं। कार का रियर सेक्शन करीब-करीब मौजूदा मॉडल जैसा ही दिया जाएगा।

इसके नंबर प्लेट पॉजिशन में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कार का इंटीरियर पहले जैसा ही रखा जाएगा और इसके टॉप वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ भी दिया जा सकता है।

न हों परेशान, यहां बदले जा सकते हैं 200 और 2000 के कटे-फटे नोट

नई दिल्ली। बीते दिनों खबर आई थी कि आप 200 और 2000 रुपए के कटे-फटे नोटों को बैंकों में बदल या जमा नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंकों (आरबीआइ) के नियमों के अनुसार नोटबंदी के बाद जारी किए गए ये नोट यदि कट-फट जाते हैं तो इनको बदला नहीं जा सकता है। मीडिया में आई खबरों में आरबीआइ के हवाले से कहा गया था कि मौजूदा नियमों के तहत केवल 5, 10, 20, 50, 100, 500, 100, और 10,000 रुपए के नोट ही बदले जा सकते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। यदि आपके पास मौजूद 200 या 2000 रुपए का नोट कट-फट या पुराना हो गया है तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आरबीआइ ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इन नोटों की आसानी से बदला जा सकता है।

यहां बदले जा सकते हैं कटे-फटे नोट

आरबीआइ के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने कटे-फटे पुराने नोट आसानी से बदल सकता है। आरबीआइ के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास मौजूद 200 और 2000 रुपए का नोट कट-फट जाता है या फिर रंग लग जाता है तो वह रिजर्व बैंक की किसी भी शाखा से इन नोटों को बदल सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार कटे-फटे या रंग लगे नोटों को रिजर्व बैंक की शाखा के अलावा करेंसी चेस्ट वाली किसी भी शाखा में बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक का कहना है कि यदि किसी नोट पर रंग या स्याही भी लग गई है तो उसे बैंक में भी बदला जा सकता है।

दो से अधिक टुकड़े होने पर भी न हों परेशान

रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि आपके पास मौजूद 200 और 2000 रुपए के नोट के यदि दो से अधिक टुकड़े हो गए हैं तो भी आपको परेशान होने की जरुरत नहीं हैं। इन नोटों को भी बदला जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। आरबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसके लिए गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारी के अनुसार, नियमों में बदलाव के कई स्तर की अनुमति लेनी पड़ती है। अधिकारी के अनुसार दीमक लगे हुए और जले हुए नोट भी बदले जाएंगे। हालांकि, इसके लिए नोट का नंबर सुरक्षित होना जरूरी है।

निवेशक गोल्ड ईटीएफ से ज्यादा इक्विटीज को दे रहे प्राथमिकता

नई दिल्ली। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) से निवेशकों की बेरुखी बदस्तूर जारी है। इस वर्ष अप्रैल में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से 54 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिक्री कर ली। आंकड़ों के मुताबिक निवेशक गोल्ड ईटीएफ की जगह इक्विटीज में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया (एम्फी) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक गोल्ड फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) मार्च के 4,806 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर अप्रैल में 4,802 करोड़ रुपये रह गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान गोल्ड ईटीएफ को लेकर निवेशकों ने बेहद सुस्त प्रतिक्रिया दी है। वित्त वर्ष

2017-18 में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से 835 करोड़ रुपये, 2016-17 में 775 करोड़ रुपये, 2015-16 में 903 करोड़ रुपये, 2014-15 में 1,475 करोड़ रुपये और 2013-14 में 2,293 करोड़ रुपये की निकासी की थी। हालांकि वित्त वर्ष 2012-13 में निवेशकों ने इस सेग्मेंट में 1,414 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

मॉर्निंगस्टार मैनेजर के रिसर्च डायरेक्टर कौस्तुभ बेलापुरकर ने कहा, ह्यवर्ष 2005 के बाद सोने के भाव में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई और 2011 के बाद इसने नई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन वर्ष 2012 में यह तेजी से गिरा। दूसरी तरफ, पिछले कुछ समय में इक्विटीज बाजार ने तेज छलांग लगाई है।

क्या होता है गोल्ड ईटीएफ

मोटे तौर पर गोल्ड ईटीएफ किसी कंपनी के स्टॉक्स की तरह होते हैं और इनमें खरीद-बिक्री भी किसी कंपनी के स्टॉक्स की तरह ही होती है। इनमें निवेश सोने के मौजूदा बाजार भाव के आधार पर होता है और शेयर बेचने पर राशि भी उसी आधार मिलती है।

भोजन, ईंधन की महंगाई से थोक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 3.18 फीसदी

नई दिल्ली। खाने-पीने की चीजों और ईंधन (पेट्रोल-डीजल, गैस) की कीमतों में तीव्र वृद्धि से देश की थोक महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 3.18 फीसदी रही, जो कि इसके पिछले महीने 2.47 फीसदी पर थी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़े के मुताबिक, पिछले महीने मुद्रास्फीति की दर हालांकि साल-दर-साल आधार पर कम रही। साल 2017 के अप्रैल में यह 3.85 फीसदी पर थी। मंत्रालय द्वारा साल 2018 के अप्रैल के लिए जारी समीक्षा में कहा गया है, मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित सालाना मुद्रास्फीति की दर अप्रैल में 3.18 फीसदी (अनंतिम) रही, जबकि मार्च में यह 2.47 फीसदी (अनंतिम) और पिछले साल के अप्रैल में 3.85 फीसदी थी। क्रमिक आधार पर, समीक्षाधीन माह में प्राथमिक वस्तुओं पर खर्च में 1.41 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो मार्च में 0.24 फीसदी थी। प्राथमिक वस्तुओं का डब्ल्यूपीआई में भार 22.62 फीसदी है। प्राथमिक वस्तुओं में खाने-पीने की चीजों का सूचकांक में भार 15.26 फीसदी है। इसमें अप्रैल में 0.87 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि मार्च में इसमें 0.29 फीसदी की गिरावट आई थी। ईंधन और बिजली के खर्च का सूचकांक में भार 13.15 फीसदी है। इसमें अप्रैल में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई है, जोकि 7.85 फीसदी रही, जबकि मार्च में यह 4.70 फीसदी थी। इसी प्रकार से समीक्षाधीन महीने में विनिर्मित उत्पादों पर खर्च में 3.11 फीसदी की वृद्धि हुई है, जोकि मार्च में 3.03 फीसदी थी। साल-दर-साल आधार पर अप्रैल में प्याज की कीमतों में काफी तेज 13.62 फीसदी की वृद्धि हुई और आलू की कीमतों में सर्वाधिक 67.94 फीसदी की वृद्धि हुई। ईंधन की कीमतों में हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अप्रैल में क्रमशः 13.01 फीसदी और 9.45 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

फर्जी तरीके से गोदनाम लेकर नौकरी पाने का मामला

निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष की जांच शुरू

गाजियाबाद। फर्जी तरीके से गोदनाम लेकर नौकरी पाने का मामला नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरेंद्र नागर की गले की हडडी बनने जा रहा है। नगर निगम कर्मचारी संघ हरेंद्र नागर द्वारा गोदनाम लेकर नौकरी पाने की शिकायत मंडलायुक्त से की है। मंडलायुक्त ने पूरे मामले की जांच अपर नगरायुक्त को सौंपी है। अपर नगरायुक्त नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एक बार फिर से चर्चाओ में आ गए है। शिकायत पत्र के अनुसार नगर निगम में लिपिक पद पर कार्यरत कर्मचारी फर्जी गोदनामा बनवाकर अपने ताऊ की मृत्यु के बाद गोदनाम तैयार कर नगर निगम में नौकरी हासिल कर लिया। फर्जी गोदनाम के आधार पर नौकरी पाने का मामले की गूंज मंडलायुक्त के पास पहुंची है। मंडलायुक्त ने पूरे मामले की जांच अपरनगरायुक्त को सौंपी है। नगर निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष पद का कार्यकाल 2020 को पूरा होना है और यह

प्रकरण हरेंद्र नागर के लिए मुसीबत बन सकता है।

नगर निगम सूत्रों का कहना है कि उक्त कर्मचारी अध्यक्ष पद रौब के चलते मलाई वाले तीन तीन स्थानों पर तैनाती लिए हुए है। शहर में निजी मकान होने पर भी नगर निगम से भवन आवंटित कराए हुए है। इस पूरे प्रकरण में मण्डलायुक्त से शिकायत की जा चुकी है। मंडलायुक्त ने अपरायुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस मामले में मण्डलायुक्त द्वारा नगरायुक्त से जांच आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए जा चुके है।

मगर नगर निगम में अधिकारियों को कमी होने के कारण से यह जांच अभी तक अधूरी थी मगर जैसे निगम में अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ वैसे ही उक्त मामले में करवट बदल ली है। इस संबंध में यूनियन अध्यक्ष हरेन्द्र नागर का कहना है कि ऐसी शिकायतें तो होती रहती है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

गौरतलब है कि फर्जी मार्कशीट जमा कर नगर निगम में नौकरी हासिल करने का यह पहला मामला नहीं है, नगर निगम में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी कर रहे हैं। यह प्रकरण नगरायुक्त के पास पहले ही पहुंच चुका है, यही वजह है कि नगरायुक्त ने विभागीय पदोन्नति पर रोक लगा दी है। नगर निगम जांच में लगा है जांच के बाद ही विभागीय पदोन्नति होगी।

जिंदगी में संयम का महत्व बताता है रमजान

नई दिल्ली। इस्लामिक कैलेंडर का नौंवा महीना रमजान का होता है। इस माह में जो भी बालिग है, रोजा रखना उसका फर्ज है। पूरे माह हर रात तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। इसको पढ़ना सुन्नत माना गया है। एक चांद दिखने पर जहां रोजा शुरू होता है, वहीं दूसरा चांद देखकर रमजान का माह खत्म होता है। उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। रमजान का पाक माह जीवन में संयम का महत्व बताता है। रोजा में खाने-पीने के साथ हर ख्वाहिशों से दूर रहना होता है। इसके साथ ही लड़ाई-झगड़े, बुरे बर्ताव से बचना होता है। अल्लाह पर यकीन रखते हुए खुद को बुराइयों से रोकना है और इबादत की आदत दिनचर्या में शामिल करनी है। बुराइयों से दूर रहने और नेक कामों में लगे रहने की प्रक्रिया को तकवा कहते हैं। इस बार सुबह चार बजे से शाम सात बजे तक रोजा रहेगा। 15 घंटे तक खाली पेट रहने से मुंह से हल्की सी बदबू आएगी, लेकिन रोजेदार के मुंह की बदबू जीवन में खुशबू लाती है। कयामत के दिन जब कब्र से उठेंगे तो कब्र से खुशबू आएगी। इस माह में सबके साथ अच्छा बर्ताव करें।

गुड न्यूज : फैमिली पेंशन पर विवाहित बेटियों का भी हक

नई दिल्ली। पिता की मौत के बाद सरकार से मिलने वाली फैमिली पेंशन से विवाहित बेटी को वंचित नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है।

न्यायाधिकरण के सदस्य के.एन. श्रीवास्तव ने ममता देवी के हक में फैसला देते हुए यह टिप्पणी की है। महिला अपने पति से अलग रह रही है। न्यायाधिकरण ने रेलवे को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को उस दिन से फैमिली पेंशन दे जब से बंद किया गया है। न्यायाधिकरण ने रेलवे के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत वर्ष 2013 में कानून में किए गए संशोधन के बाद याचिकाकर्ता को मिलने वाली फैमिली पेंशन को बंद कर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने कहा है कि कानून में संशोधन के तीन साल बाद

याचिकाकर्ता को मिलने वाली पेंशन रद्द करना एकतरफा कार्रवाई है। फिरोजाबाद निवासी ममता के पिता भीम सेन रेलवे में वर्ष 1978 से गैंगमेन की नौकरी कर रहे थे। वर्ष 2005 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के करीब तीन साल बाद जनवरी, 2008 से ममता व उनके दो भाइयों को फैमिली पेंशन मिलने लगी। इस बीच पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया गया। इसके करीब तीन साल बाद रेलवे ने नियमों का हवाला देकर ममता की पेंशन बंद कर दी।

स्कूलों में लगेंगे 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरे, माता-पिता घर से रख सकेंगे नजर

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राज्य के 1,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में अगले छह महीनों में 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिनकी कुल लागत 597.51 करोड़ रुपये होगी। ये सीसीटीवी कैमरे शौचालयों को छोड़कर कक्षाओं और खुले स्थानों में लगाए जाएंगे।

जैन ने कहा कि इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है और सात से आठ कंपनियों ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने कहा कि 1,46,800 सीसीटीवी कैमरे 1,028 नगरीय सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे।

सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक स्कूल में सुरक्षित रखी जाएगी और 30 दिनों के बाद स्वतः नष्ट हो जाया करेगी। अभिभावकों को एक आईडी और पासवर्ड जारी किया जाएगा, जिसकी सहायता से वे रिकॉर्डिंग देख सकेंगे।

जैन ने कहा कि कुल राशि में से 385.85 करोड़ रुपये परियोजना के क्रियान्वयन पर व्यय होंगे, 57.69 करोड़ रुपये कैमरों के रखरखाव तथा 154.97 करोड़ रुपये स्कूलों को इंटरनेट सुविधा देने पर खर्च होंगे। इस परियोजना को दिल्ली सरकार की व्यय वित्त कमेटी ने मंजूरी दी है।

वहीं, शहर में महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच नया विवाद बनकर उभरी है।

बैजल ने इस परियोजना की जांच के लिए एक समिति गठित की है जबकि आम आदमी पाटी (आप) सरकार ने उपराज्यपाल को इस परियोजना से दूर रहने के लिए कहा है। प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया है कि समिति का गठन परियोजना में विलंब करने के लिए हुआ है।

महानगर में इलेक्ट्रिक बसें व आटो चलाने की कवायद शुरू

जीडीए में एस्सेल इंफ्रा कंपनी ने दी प्रजेंटेशन, 15 दिन में बजट सहित डीपीआर देगी

गाजियाबाद। महानगर में इलेक्ट्रिक बस और ऑटो का संचालन करने के लिए जीडीए ने कवायद शुरू कर दी है। बुधवार को एस्सेल इंफ्रा कंपनी ने इसको लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया। प्रजेंटेशन में चार रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही महानगर में इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने का प्रस्ताव भी शामिल है। जीडीए उपाध्यक्ष ने कंपनी से प्रोजेक्ट का बजट सहित विस्तृत डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है।

शहर को पर्यावरण मुक्त करने तथा यातायात व्यवस्था दुरूस्तकरने के लिए बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एस्सेल इंफ्रा कंपनी ने शहर में इलेक्ट्रिक बस और ऑटो चलाने का प्रजेंटेशन दिया। इस प्रजेंटेशन में पहले चरण में शहर की चार सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह भी बताया गया कि शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने और प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों से यातायात बेहतर विकल्प है। ऐसे में गाजियाबाद में भी इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाई जा सकती है। प्रजेंटेशन में दिलशाद गार्डन से लालकुआं, कौशांबी से मोरटा, कौशांबी से लालकुआं, भोपुरा से मोरटा तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही पूरे शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। जीडीए उपाध्यक्ष रितु माहेश्वरी ने कंपनी को इस प्रोजेक्ट के बजट सहित विस्तृत डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

कंपनी 15 दिन में इसकी विस्तृत डीपीआर जीडीए को सौंपेगी। इस दौरान मुख्य अभियंता विवेकानंद सिंह, एसएस वर्मा, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

हर रूट पर होंगे 18 तक बस स्टाप

पहला रूट दिलशाद गार्डन से मोहननगर, नया बस अड्डा, पुराना रेलवे स्टेशन और लाल कुआं तक कुल 15 किमी का रूट होगा। इसमें हर किमी पर एक बस स्टाप बनाया जाएगा। इस तरह कुल 15 बस स्टाप बनाए जाने की योजना है। दूसरा रूट कौशांबी से वैशाली, वसुंधरा, मोहननगर, नया बस अड्डा, पुरान बस अड्डा, हापुड़ चुंगी, राजनगर एक्टेंशन होते हुए मोरटा तक जाएगा। कुल 23 किमी लंबा रूट में 18 बस स्टाप होंगे। तीसरा रूट कौशांबी से वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, एबीईएस कॉलेज से लाल कुआं तक बनेगा। 20 किमी लंबा रूट में 14 बस स्टाप बनेंगे। चौथा रूट भोपुरा से हिंडन चौक, मोहननगर, नया बस अड्डा, पटेल नगर, राजनगर, राजनगर एक्सटेंशन से होता हुआ मोरटा तक होगा। इस 19 किमी लंबा रूट में 14 बस स्टाप बनाने का प्रस्ताव है।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने होंगे 1000 करोड़

नई दिल्ली। जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. (जेएएल) को एक हजार करोड़ रुपये 15 जून तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास जमा कराने होंगे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह रकम जमा कराने के बाद जेएएल की सहयोगी कंपनी जयप्रकाश इंफ्राटेक को नीलाम करने की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जेएएल को दो हजार करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था, जिससे घर खरीदारों को पैसा लौटाया जा सके। कंपनी ने 750 करोड़ रुपये जमा करा दिए थे। अब उसे फिर से रकम जमा कराने का आदेश दिया गया है। रियल एस्टेट फर्म की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनुपम लाल दास ने कहा कि जयप्रकाश इंफ्राटेक को फिर से जिंदा करने के प्रस्ताव पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) गौर करे। चीफ जस्टिस की बेंच ने एमीकस क्यूरी पवनश्री अग्रवाल से कहा कि जो पैसा रियल एस्टेट कंपनी जमा करा रही है, वह घर खरीदारों को लौटाया जाए। एक वित्तीय संस्था की तरफ से पेश वकील सीए सुंदरम ने बेंच से कहा कि ज्यादातर खरीदारों ने बैंकों से लोन लेकर कंपनी में पैसा जमा कराया है। कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे बैंकों का पैसा लौट सके। घर खरीदारों की तरफ से पेश वकील अजीत सिन्हा ने कहा कि कोर्ट ने कंपनी को दो हजार करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था, लेकिन अभी तक कुल 750 करोड़ रुपये ही जमा कराए गए।

धक-धक गर्ल के दीवाने थे लाखों, लेकिन इस सिंगर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के देश में कई लोग फैन हैं. धक धक गर्ल ने हमेशा अपनी एक्टिंग और अपने डांस से दर्शकों का मनोरंजन किया है और दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था जब उनके पेरेंट्स द्वारा उनका रिश्ता मशहूर सिंगर सुरेश वाडकर को भेजा गया था लेकिन सुरेश ने इस शादी के लिए इंकार कर दिया था. अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने इतनी पॉपुलर और सुपरहिट एक्ट्रेस से शादी करने से इंकार कर दिया. दरअसल, हमारी सहयोगी वेबसाइट इंडिया.कॉम में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक सुरेश ने इस शादी से इसलिए इंकार किया था क्योंकि उस वक्त माधुरी काफी पतली थीं. गौरतलब है कि माधुरी उस वक्त काफी फेमस हो गईं थी और कई फिल्मों में काम कर रही थीं, जिस वजह से उनके पेरेंट्स को उनकी शादी को लेकर काफी चिंता थी. जिसके बाद उन्होंने सिंगर सुरेश वाडकर को माधुरी की शादी का प्रपोजल भेजा था. हालांकि, उन्होंने इस रिश्ते को माधुरी के पतले होने की वजह से ठुकरा दिया था. हालांकि, इस वजह से माधुरी ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा. माधुरी लगातार फिल्मों में काम करती रहीं और 6 फिल्मफेयर अवॉर्ड और एक पद्मश्री अवॉर्ड अपने नाम किया.

माधुरी दीक्षित को आज तक 14 बार फिल्मफेयर के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है. इसके अलावा उन्होंने साल 1999 में डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी की थी. दोनों के दो बच्चे अरिन और रयान हैं. वहीं वर्क फ्रंट पर बात करें तो वह जल्द ही मराठी सिनेमा में फिल्म बकेट लिस्ट से डेब्यू करने वाली हैं.

कठुआ गैंगरेप मामले की वकील दीपिका के समर्थन में आईं हॉलीवुड एक्ट्रेस एमा वाटसन

'हैरी पॉटर' फेम अभिनेत्री एमा वाटसन ने कठुआ बलात्कार पीडिता की वकील दीपिका सिंह रजावत के समर्थन में ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि दीपिका को पूरी ताकत मिले. उन्होंने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से ठीक पहले दीपिका की वायरल हो रही फोटो को भी ट्वीट में साझा किया है. एमा वाटसन यूनाइटेड नेशन्स वूमेंस गुडविल एंबेसेडर हैं. उनके ट्वीट पर दीपिका ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने डीएनए से बातचीत में कहा,' उनके ट्वीट से मुझे खुशी मिली है, लेकिन मुझे तब ज्यादा खुशी होगी जब मासूम बच्ची को न्याय मिलेगा. इस केस को लड़ने पर धमकियां मिल रही है, लेकिन वो बहादुरी से इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं. एमा के ट्वीट पर उन्होंने कहा,' उनके ट्वीट से प्रोत्साहन और समर्थन मिला है. इससे पता चलता है कि लोग हमारे साथ हैं और मासूम के लिए न्याय चाहते हैं. चूंकि दीपिका मानवाधिकारों से जुड़े केस ही लड़ती हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों के हक से जुड़ी, इसलिए उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है. एक वकील के घर में एक बच्ची की मौत के बाद जब उस मुद्दे को दीपिका ने उठाया था, तो बार एसोसिएशन ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. आपको बता दें कि जनवरी में कश्मीर के कठुआ में आठ लोगों ने 8 साल की मासूम बच्ची को बंधक बनाकर कई दिनों तक उसके साथ गैंगरेप किया था. बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी. इस केस की जिम्मेदारी क्राइम ब्राईट के पास है. क्राइम ब्रांच ने आठों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर ली है.

नागिन-3 में इच्छाधारी नागिन के रोल में नजर आएंगी करिश्मा तन्ना

टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना छोटे पर्दे का काफी फेमस चेहरा हैं। साल 2001 से करियर की शुरूआत करने वाली करिश्मा कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। उन्हें खास पहचान 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से मिली थी। इसके बाद उन्हें साल 2004 में बिग बॉस हाउस में देखा गया। तब से करिश्मा किसी ने किसी सीरियल में लगातार नजर आ रही हैं। इस साल करिश्मा कलर्स चैनल पर शुरू होने वाले शो 'नागिन–3' में नजर आने वाली हैं। अपने सीरियल के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय बेहद खुशी हुई जब बालाजी टेलीफिल्म्स ने उन्हें लोकप्रिय सुपरनैचुरल शो 'नागिन' के तीसरे सीजन में इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया। निमार्ता एकता कपूर ने अप्रैल में सोशल मीडिया पर करिश्मा के 'नागिन–3' का हिस्सा बनने की जानकारी दी थी। करिश्मा ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, 'बालाजी ने जब मुझे प्रस्ताव दिया, तो यह अभिभूत कर देने वाला था क्योंकि मैं उन लोगों के साथ लंबे समय के बाद काम करने जा रही थी। मैंने अपने करियर की शुरूआत उनके साथ की, तो जब मुझे बालाजी से फोन आया, यह एक सपना सच होने जैसा था। यह मेरे लिए एक तरह से फिर से परिवार के साथ काम करने जैसा था।' करिश्मा एक अच्छी कहानी वाले शो की तलाश में थीं। उन्होंने कहा कि एक ही तरह का किरदार निभाने से एक तरह का ठहराव महसूस होता है। हमारे पास अभिनय करने के लिए किरदार कुछ दिलचस्प होना चाहिए। बतौर 'नागिन' वह दूसरी बार छोटे पर्दे पर नजर आने जा रही हैं, इससे पहले वह 'नागाजुर्न–एक योद्धा' में नजर आ चुकी हैं।

आईपीएलः और विराट हुए कोहली, यह मुकाम हासिल करने वाले बने पहले खिलाड़ी

अपने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के मैच में मेजबान किंग्स इलेवन पंजाब को 10 विकेटों से करारी मात देकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को एक बार फिर हवा दे दी है।

अपने दूसरे घर होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही पंजाब की टीम बैंगलोर के नियंत्रित गेंदबाजी आक्रमण के सामने 15 ओवरों में 88 रनों पर ही ढेर हो गई। इस आसान से लक्ष्य को बेंगलोर ने 8.1 ओवरों में बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। विराट कोहली ने इस मैच में शानदार 48 रन बनाए जिसकी मदद से उन्होंने खास मुकाम हासिल कर लिया है।

विराट-पार्थिव ने आसानी से किया लक्ष्य का पीछा

कप्तान विराट कोहली इस मैच में पार्थिव पटेल के साथ पारी की शुरूआथ करने आए और नाबाद लौटे। कप्तान ने 28 गेंदों की पारी में छह चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 48 रन बनाए। पटेल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ दिया और 22 गेंदों में सात चौकों की मदद से नाबाद 40 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल रहे। विराट ने इस पारी के दौरान इस आईपीएल सत्र में भी 500 रनों का आकड़ा पार कर लिया है।

कोहली ने बनाया यह रिकॉर्ड

विराट कोहली ने इस सत्र में भी 500 रन पुरे किए, उनके इस सत्र में 514 रन हो गए हैं। विराट ने पांच आईपीएल सत्रों में 500 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करने वाले वो इकलौते खिलाड़ी हैं। डेविड वार्नर ने 500 रनों का अकड़ा 4 बार छुआ है। 3 बार 500 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सुरेश रैना , गौतम गंभीर और क्रिस गेल का नाम है। विराट ने एक सत्र में सर्वाधिक रन 2016 सत्र में बनाए थे। उन्होंने उस सत्र में 16 मैचों में 973 रन बनाए थे।

बनाए रखी प्ले ऑफ में जाने की उम्मीद

बैंगलोर को अब अगर अंतिम–4 में जगह बनानी है तो उसे बाकी के बचे दोनों मैच जीतने होंगे साथ ही अन्य टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना होगा। इस मैच में हार उसे पूरी तरह से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ ही बड़े अंतर से जीत दर्ज कर कोहली की टीम ने अपना नेट रन रेट भी सुधारा है जोकि प्ले ऑफ की दौड़ में बहुत सहायक होगा।

इस बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं बॉलीवुड सिंघम 'अजय देवगन'

बॉलीवुड के सिंघम और एक्टर अजय देवगन इन दिनों काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं। दरअसल, इस समय वो अपनी आगामी फि ल्म 'टोटल धमाल' की शूटिंग में काफी व्यस्त चल रहे हैं और इसी बिजी शेड्यूल के कारण उन्हें तेज दर्द की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अजय देवगन 'टेनिस एल्बो' की समस्या से ग्रसित हैं। यहीं नहीं, इस बिमारी का इलाज कराने के लिए उन्हें जर्मनी भी जाना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि अजय को बेहद तकलीफ में देख, उनके को-स्टार अनिल कपूर ने उन्हें जर्मनी जा कर वहां इलाज कराने की सलाह दी है। हाल ही में अनिल कपूर भी 'टेनिस एल्बो' की समस्या से काफी परे शान थे।

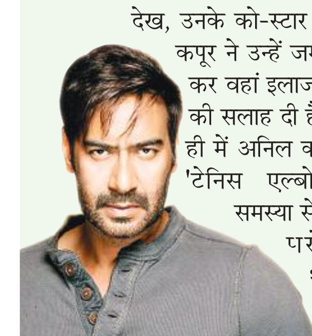

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह